उत्पादकों को राज्य-वार गन्ने की कीमत की कितनी राशि देनी बकाया है; और

(ख) इस वर्ष चीनी मिलों को हुए असाधारण लाभ को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि दिलाने तथा भविष्य में ठीक समय पर राशि का भुगतान करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 31 मार्च, 1968 को राज्यवार चीनी मिलों द्वारा दिये गन्ने के मूल्य का बकाया बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-1137 68]

(ख) राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में पत्र-व्यवहार किया गया था; पिछले मौसमों के बकाये के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि दोषी मिलों को उपलब्धि सर्टिफिकेट जारी किया गया है। चालू मौसम 1967-68 के संबंध में 31 मार्च, 1968 को स्थिति यह थी कि गन्ना उत्पादकों को देय 236.4 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 207.5 करोड़ रुपये उस तारीख तक दे दिये गये थे। चालू मौसम के बकाये को भी शीघ्र चुका देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कृषि सम्बन्धी वार्षिक कैलेन्डर

9307. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ब्यौरे वार कृषि सम्बन्धी वार्षिक कैलेन्डर बनाने का विचार है जिससे किसानों को बीज, रासायनिक उर्वरकों के उचित प्रयोग और अधिक उपज वाली फसलों आदि के बारे में नवीनतम तथा अधिकृत सूचना मिल सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही होता।

(क) स्थान-स्थान की कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में इतना अधिक अन्तर है कि देश के समस्त क्षेत्रों की समस्त फसलों के लिए एक कैलेन्डर तैयार करना सम्भव नहीं है। राज्य सरकारें कृषकों के लिए ऐसे कैलेन्डर गाइड तैयार करती हैं, जिन में कृषकों के प्रयोग हेतु विभिन्न फसलों के लिए सुधरी कृषि विधियां व अन्य लाभप्रद जानकारी दी जाती है।

फिर भी खाद्य और कृषि मन्त्रालय (विस्तार निदेशालय) समस्त प्रमुख फसलों के विषय में और विशेषकर उन अधिक उत्पादनशील किस्मों के बारे में, पुस्तिकायें आदि प्रकाशित करता है, जिनके विषय में प्रयोग तथा अनुभव के आधार पर पैकेज की विधियों का विकास हुआ है। इसी प्रकार का साहित्य, जिसमें स्थानीय सिफारिशें भी शामिल होती हैं, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

Supply of Tractors

9308. SHRI MOHAN SWARUP : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2303 on the 29th February, 1968 and to state :

(a) whether it is a fact that hundreds of farmers requiring 50 H. P. tractors are on long waiting lists ; and

(b) if so, the reasons for not importing 50 H. P. tractors this year from U. S. S. R. to bridge the increased gap for their demand and supply, when the indigenous production is not likely to meet the overall demand ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Demand has been indicated already in reply to Unstarred Question No.

2303 answered in the Lok Sabha on the 29th February, 1968.

(b) A production of 2,500 tractors in the range of 50 HP is expected during 1968-69 and of 3,500 numbers in 1969-70. To achieve the above target, the firm, Messers Hindustan Tractors Ltd., has been licensed adequately for import of c.k.d. packs and raw materials. The firm has been allowed to import 3,000 c. k. d. packs during 1967. With this the availability of tractors will be stepped up. The pending demand of such tractors is expected to be fully met by the tractors to be produced in the country during 1968-69. In these circumstances, it is not considered advisable or necessary to go in for the import of 50 HP tractors from U.S.S.R.

Import of Czech Tractors

9309. SHRI MOHAN SWARUP : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of Czech 20 H. P. tractors imported so far and their allocations, State-wise, to Agro-Industries Corporations ;

(b) the number of such tractors sold so far to farmers by each Corporation separately ;

(c) the details of after-sales service rendered, if any, to such tractors, whether directly by the Corporations or through third parties and with what set-up in both the cases ; and

(d) whether it is a fact that Agro-Industries Corporation, Madras has declined to handle sales of Czech Tractors and if so, on what grounds ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) 1,000 tractors have so far been imported. Following allocations were made to the State Agro Industries Corporations :

Punjab	300
Haryana	200
U. P.	200
Bihar	300

(b) Following tractors have so far been sold by the respective Corporations :

Punjab	290
Haryana	200
U. P.	95
Bihar	(Only one hundred tractors arrived some time back in each case; balance has just arrived).

(c) Following after sale service arrangements have been made by the respective Corporations :

(i) Punjab : The Punjab Corporation has set up a base workshop with two mobile workshop units.

(ii) Haryana : The Haryana Corporation has set up a base workshop and one mobile unit. It is also organising after sale services in some districts through other parties on an *ad hoc* basis.

(iii) U. P. : The U. P. Corporation has made its own arrangements for after sale services. It is also to utilise Government Agricultural Workshops and Panchayat Udyog Workshops for undertaking this work.

(iv) Bihar : The Bihar Corporation has set up a base workshop. It is planning to organise mobile units and regional workshops for undertaking after sale service of tractors.

(d) Madras Corporation has asked for an allocation of 100 tractors for the State but in view of the limited nature of the business it was not interested in handling the sale of these tractors.

मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

9310. श्री म० च० दीक्षित : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने मुख्य स्वचालित टेलीफोन केन्द्र हैं ;

(ख) यदि हां, पर कोई मुख्य स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं है तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?